

क्रमांक:- क्र.२८२३/ प्र.क्र. ११ /२०२३/९
सामान्य प्रशासन विभाग,
५५८, विस्तार इमारत, पाचवा मजला,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.
दिनांक- ३१ जानेवारी, २०२३.

भविष्य निर्वाह निधीची वार्षिक कमाल मर्यादा रु. ५ लक्ष आणि मासिक वर्गणी एकूण वित्तलब्धीच्या ६ टक्के दराने जमा करणे या विषयाबाबत केंद्र शासनाच्या कार्मिक, लोकतक्रारी आणि सेवानिवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या सेवानिवृत्ती वेतन तथा निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाची दि.१५ जून २०२२ ची अधिसूचना तसेच ज्ञापन क्रमांक ३/१३/२०२२-P&PW(F)(८३५३) दिनांक २ नोव्हेंबर, २०२२ आणि ज्ञापन क्रमांक ३/६/२०२१- P&PW(F) दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२२ अन्वये उचित तथा तातडीच्या कार्यावाहीच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

२. राज्यातील अ.भा.से. (भा.प्र.से./ भा.पो.से./ भा.व.से.) अधिकाऱ्यासंदर्भात उचित कार्यवाही करण्यासाठी सदर सूचना याद्वारे पृष्ठांकित करण्यात येत आहेत.

३. सदर शासन पृष्ठांकन राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०१३११२४२००३३०७ असा आहे. सदर शासन पृष्ठांकन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे.

(सु. गं. गांगरकर)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
४. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
६. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
७. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
८. सर्व विभागीय आयुक्त.
९. सर्व जिल्हाधिकारी.
१०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
११. गृह विभाग/पोल-१, मंत्रालय, मुंबई.
१२. महसूल व वन विभाग / फ-४, मंत्रालय, मुंबई.
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई व नागपूर.
१४. सर्व लेखाधिकारी/ आहरण व संवितरण अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालय.
१५. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सर्व जिल्हा परिषद.
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
१५. अवर सचिव, कार्यासन १०/ कार्यासन १० अ.
१६. कक्ष अधिकारी, कार्यासन २६ (रोखा शाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१७. सहायक संचालक (लेखा)/ ९-अ.
१८. निवडनस्ती.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21072022-237410
CG-DL-W-21072022-237410

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25]	नई दिल्ली, जुलाई 10—जुलाई 16, 2022, शनिवार/आषाढ़ 19—आषाढ़ 25, 1944
No. 25]	NEW DELHI, JULY 10—JULY 16, 2022, SATURDAY/ASADHA 19—ASADHA 25, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 15 जून, 2022

सा.का.नि. 96.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) संशोधन नियमावली, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) नियम 7 में, उप-नियम (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक अंशदान का योग उस वित्तीय वर्ष में जमा की गई बकाया अंशदान की रकम के साथ नियम 8 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा।

3. उक्त नियमों के नियम 8 में-

(क) उप-नियम (1) में, खंड (ख) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि वित्तीय वर्ष में मासिक अंशदान का योग आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9घ के उप-नियम (2) के नीचे दिए स्पष्टीकरण के खंड(ग) के उप-खंड(i) में दी गई सीमा से अधिक नहीं होगा।";

(ख) उप-नियम (4) में,-

(1) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा।

(2) द्वितीय परंतुक में, 'और' शब्द को हटाया जाएगा।

(ग) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(5) उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित या उप-नियम (4) के तहत घटाई या बढ़ाई गई अंशदान की रकम उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अध्यधीन होगी";

(घ) उप-नियम (3) में उक्त नियमों के नियम 10 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक अंशदान की रकम का योग उस वित्तीय वर्ष में अंशदान की बकाया रकम और वसूल किए गए व्याज के साथ नियम 8 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट सीमा से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा।"

[फा. सं. 3/6/2021- पी & पी डब्ल्यू (एफ)]

संजय शंकर, उप सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना का.आ. 3000, तारीख 1 दिसंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्याक सा.का.नि. 234(अ), तारीख 28 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित किए गए।

1. का.आ.1814, तारीख 18.06.1988
2. का.आ.2002, तारीख 02.09.1989
3. का.आ.710, तारीख 04.03.1990
4. का.आ.3006, तारीख 17.11.1990
5. का.आ.3272, तारीख 08.12.1990

6. का.आ.146, तारीख 20.03.1993
7. का.आ.377, तारीख 10.02.1996
8. का.आ.379, तारीख 10.02.1996
9. का.आ.3228, तारीख 23.11.1996
10. का.आ.826, तारीख 25.04.1998
11. का.आ.2500, तारीख 05.12.1998
12. का.आ.2690, तारीख 16.09.2003
13. का.आ.1485(अ), तारीख 30.12.2003
14. का.आ.3682, तारीख 15.10.2005
15. का.आ.1529, तारीख 06.06.2009
16. का.आ.2689, तारीख 22.09.2009
17. का.आ.2869, तारीख 03.10.2010
18. का.आ.3091, तारीख 25.09.2012
19. का.आ.234(अ), तारीख 28.03.2014

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

New Delhi, the 15th June, 2022

G.S.R. 96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts department, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 (herein after referred to as the said rules) In rule 7, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the sum of the monthly subscriptions during a financial year together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the limit as specified in the second proviso to clause (b) of sub-rule (1) of rule 8,.

3. In rule 8 of the said rules —

(a) in sub-rule(1), in clause(b), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the sum of monthly subscriptions in a financial year shall not exceed the threshold limit referred to in sub-clause (i) of clause (c) of the Explanation below sub-rule (2) of rule 9D of the Income Tax Rules, 1962”;

(b) in sub-rule(4),—

(1) The first proviso shall be omitted;

(2) In the second proviso, the word ‘further’ shall be deleted;

(c) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(5) The amount of subscription fixed under sub-rule(3) or reduced or enhanced under sub-rule (4) shall be subject to the minimum and maximum limits specified in sub-rule(1)” ;

- (d) in rule 10 of the said rules in sub-rule (3), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the sum of the monthly subscriptions during a financial year together with arrears of subscription and the interest thereon recovered in that financial year shall, in no case, exceed the limit as specified in the second proviso to clause (b) of sub-rule (1) of rule 8”.

[F. No.3/6/2021-P&PW (F)]

SANJOY SHANKAR, Dy. Secy.

Note: - The principal rules were furnished in the Gazette of India, vide notification S.O. 3000, dated the 1st December 1960 and last amended vide number G.S.R 234 (E), dated the 28th March 2014.

1. SO No 1814 dated 18.06.1988
2. SO No 2002 dated 02.09.1989
3. SO No 710 dated 04.03.1990
4. SO No 3006 dated 17.11.1990
5. SO No 3272 dated 08.12.1990
6. SO No 146 dated 20.03.1993
7. SO No 377 dated 10.02.1996
8. SO No 379 dated 10.02.1996
9. SO No 3228 dated 23.11.1996
10. SO No 826 dated 25.04.1998
11. SO No 2500 dated 05.12.1998
12. SO No 2690 dated 16.09.2003
13. SO No 1485 (E) dated 30.12.2003
14. SO No 3682 dated 15.10.2005
15. SO No 1529 dated 06.06.2009
16. SO No 2689 dated 22.09.2009
17. SO No 2869 dated 03.10.2010
18. SO No 3091 dated 25.09.2012
19. SO No 234 (E) dated 28.03.2014

F.No. 3/6/2021-P&PW (F)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
dated: 11.10.2022

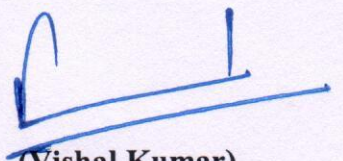
Office Memorandum

Subject:- Ceiling of Rs. 5 Lakh on subscription to General Provident Fund (GPF) in a financial year- regarding.

In accordance with General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960, the amount of subscription to the GPF in respect of a subscriber, shall not be less than 6% of the emoluments and not more than total emoluments of the subscriber. However, there was no ceiling on the total amount of subscription of a subscriber into his GPF account in a financial year.

2. Rules 7, 8 & 10 of the General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960 have been amended vide Notification No. G.S.R. 96 dated 15.06.2022. As per the said Notification dated 15.06.2022, the sum of the monthly subscription by a subscriber under the GPF during a financial years together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the threshold limit (at present Rupees Five Lakh) referred to in sub clause (i) of clause (c) of the Explanation below sub rule (2) of the rule 9D of the Income Tax Rules, 1962 [as inserted vide Notification No. G.S.R. 604 (E) dated 31.08.2021 of Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)].

3. All Ministries/Departments are requested that the above amended provisions of the GPF Rules, 1960 regarding limit of subscription under GPF in a financial year by a subscriber may be given wide publicity to all Government servants and, more particularly, to the personnel dealing with the GPF matters in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there-under, for strict implementation.


(Vishal Kumar)

Under Secretary to the Govt of India

All Ministries/Departments/Organisations
(as per standard list)

F. No. 3/13/2022-P&PW(F) (8353)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
dated: 02.11.2022

Office Memorandum

Subject:- Ceiling of Rs. 5 Lakh on subscription to General Provident Fund (Central Services) in a financial year- instructions regarding.

The undersigned is directed to say that in accordance with the General Provident Fund (Central Services), Rules, 1960, the amount of subscription to the GPF in respect of a subscriber, shall not be less than 6% of the emoluments and not more than total emoluments of the subscriber. Rules 7, 8 & 10 of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 were amended vide Notification No. G.S.R. 96 dated 15.06.2022. As per the said Notification dated 15.06.2022, the sum of the monthly subscription by a subscriber under the GPF during a financial year together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the threshold limit (at present Rupees Five Lakh) referred to in sub clause (i) of clause (c) of the Explanation below sub rule (2) of the rule 9D of the Income Tax Rules, 1962 [as inserted vide Notification No. G.S.R. 604 (E) dated 31.08.2021 of Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)].

2. Further, instructions have been issued vide this Department's OM No 3/6/2021-P&PW (F) dated 11.10.2022 for strict implementation of the above amended provisions of the General Provident Fund (Central Services), Rules, 1960.

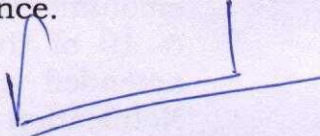
3. References have been received in this Department seeking advice as to how the GPF subscription is to be regulated in the case of those Government servants in which cases the total subscription of GPF in the current financial year (i.e 2022-23) has already exceeded the limit of Rupees Five Lakh or is likely to exceed this limit even with the minimum subscription of 6% of emoluments prescribed under General Provident Fund (Central Services), Rules, 1960.

4. The amendment Notification limiting the maximum annual GPF subscription was issued on 15.06.2022. A situation of annual total subscription exceeding the limit of Rupees Five Lakh in the current financial year would not have arisen if appropriate steps were taken immediately after the issue of the above amendment notification. However, keeping in view the difficulties being faced by the Ministries/Departments, the matter has been examined and the following further instructions are issued in this regard:

(a) In the case of those Government servants, whose GPF subscription during the current financial year (i.e. 2022-23) has already exceeded the threshold limit of Rs. 5 lakhs, no further deduction of GPF subscription may be made from their salary in the current financial year. In those cases, the provision regarding minimum monthly subscription of 6% of the emoluments shall be deemed to have been relaxed.

(b) In the case of those Government servants, whose GPF subscription during the current financial year (i.e. 2022-23) has not yet reached/exceeded the threshold limit of Rs. 5 lakh, further deductions towards GPF subscriptions during the current financial year may be phased out in such a manner that the total subscription during the current financial year does not exceed Rs. 5 lakh. In cases where the total contribution is likely to exceed Rs. 5 lakh even with minimum monthly subscription of 6% of the emoluments, deduction of GPF subscription from the salary may be stopped as soon as the total contribution in the current financial year reaches Rs. 5 lakh. In such cases also, the provision regarding minimum monthly subscription of 6% of the emoluments shall be deemed to have been relaxed.

5. All Ministries/Departments are requested to bring the above instructions to the notice of the all concerned for strict compliance.


(Vishal Kumar)

Under Secretary to the Govt of India

**All Ministries/Departments/Organisations
(as per standard list)**